

International Journal of

Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

व्यावसायिक फसल विकास के लिए संस्थागत ऋण की भूमिका पर एक विश्लेषणात्मक जांच: उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के विशेष संदर्भ में

(An Analytical Investigation on the Role of Institutional Credit for Commercial Crop Development: With Special Reference to Basti District of Uttar Pradesh)

1शिव कुमार मौर्या

शोध छात्र अर्थशास्त्र एवम् ग्रामीण विकास विभाग, डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या (यू. पी.)

²डॉ. मृदुला मिश्रा

प्रोफेसर,अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास विभाग डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या (यू. पी.)

³ शालिनी सिंह

शोध छात्रा, अर्थशास्त्र एवम् ग्रामीण विकास विभाग, डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या (यू. पी.)

Corresponding Author: शिव कुमार मौर्या, Email Id: mauryajisk92@gmail.com

सारांश: कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है जो न केवल ग्रामीण रोजगार प्रदान करती है बल्कि खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तर प्रदेश, भारत का एक प्रमुख कृषि राज्य है, जहाँ विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। इनमें से व्यावसायिक फसलें, जो मुख्यतः बाजार-उन्मुख होती हैं, विशेष महत्व रखती हैं। व्यावसायिक फसलों के विकास में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से संस्थागत ऋण, एक निर्णायक भूमिका निभाती है। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में व्यावसायिक फसल विकास में संस्थागत ऋण की भूमिका का विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

मुख्य शब्द: व्यावसायिक फसलें और ऋण (Commercial Crops and Credit), संस्थागत ऋण (Institutional Credit), बस्ती जनपद में व्यावसायिक फसलें (Commercial crops in Basti district)



ı. परिचय

उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में व्यावसायिक फसलों के विकास में संस्थागत ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यवसायिक फसलें, जैसे गन्ना, तम्बाकू, फल, सिब्जियाँ और फूल, किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करती हैं। संस्थागत ऋण किसानों को उन्नत तकनीकों, बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधाओं, और कृषि यंत्रों में निवेश करने में मदद करता है, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। बस्ती जनपद में अधिकांश किसान लघु और सीमांत श्रेणी के हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और जो मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहते हैं। संस्थागत ऋण की उपलब्धता और प्रभाव का अध्ययन आवश्यक है तािक यह समझा जा सके कि यह ऋण कैसे किसानों की व्यवसायिक फसलों की खेती में सहायक हो सकता है। हालांकि, ऋण प्राप्त करने में कई चुनौतियाँ भी हैं, जैसे जागरूकता की कमी, जिटल प्रक्रियाएँ, गारंटी की आवश्यकताएँ, और समय पर ऋण की उपलब्धता। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, ऋण प्रक्रिया का सरलीकरण और समय पर ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। संस्थागत ऋण का प्रभावी उपयोग बस्ती जनपद के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है और क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

1.1 संस्थागत ऋण का महत्व

संस्थागत ऋण, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के लिए, किसानों को आवश्यक वित्तीय संसाधन प्रदान करता है जिससे वे बेहतर कृषि तकनीकों, उन्नत बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यक संसाधनों का उपयोग कर सकें। कई अध्ययन इस तथ्य की पृष्टि करते हैं कि संस्थागत ऋण से कृषि उत्पादन में सुधार होता है। सियाल, अवान, और वकास (2011) ने पाकिस्तान में समय श्रृंखला विश्लेषण के माध्यम से पाया कि संस्थागत ऋण ने कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इसी तरह, फरीदी, चौधरी, और ताहिर (2015) ने भी पाकिस्तान में पाया कि संस्थागत ऋण कृषि उत्पादकता में महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण बना।

1.2 भारतीय संदर्भ में संस्थागत ऋण

भारत में कृषि ऋण की स्थिति और इसके प्रभाव पर भी व्यापक शोध किया गया है। कुमार, सिंह, और सिन्हा (2010) ने भारत में कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की स्थिति, प्रदर्शन और निर्धारकों का विश्लेषण किया और पाया कि संस्थागत ऋण ने कृषि उत्पादन और किसानों की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। अहंगर, गनी, और पैडर (2013) ने भी अपने अध्ययन में पाया कि भारत में संस्थागत ऋण ने कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1.3 बस्ती जनपद में व्यावसायिक फसलें और ऋण की भूमिका

बस्ती जनपद उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जहाँ व्यावसायिक फसलों की खेती व्यापक रूप से की जाती है। यहाँ के किसानों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मौसम की अनिश्चितता, बाजार की अस्थिरता और वित्तीय संसाधनों की कमी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए संस्थागत ऋण एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरता है।



खालिद बशीर और महमूद (2010) ने पाकिस्तान के लाहौर जिले में चावल उत्पादकता पर संस्थागत ऋण के प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि ऋण की उपलब्धता ने किसानों को बेहतर उत्पादन तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम बनाया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई । इसी तरह, हुसैन, अली, बिलाल, और नवाज़ (2015) ने अपने अध्ययन में पाया कि पाकिस्तान में संस्थागत ऋण ने कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव डाला।

1.4 अध्ययन का उद्देश्य एवं महत्व

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बस्ती जनपद में व्यावसायिक फसल विकास में संस्थागत ऋण की भूमिका का विश्लेषण करना है। विशेष रूप से, यह अध्ययन बस्ती जनपद में संस्थागत ऋण की स्थिति, प्रभाव, और चुनौतियाँ पर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेगा।

साहित्य की समीक्षा

संस्थागत ऋण के प्रभाव पर विभिन्न अध्ययन यह दर्शाते हैं कि यह कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार का एक प्रमुख साधन है। अयाज़ और हुसैन (2011) ने पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले में पाया कि संस्थागत ऋण ने कृषि क्षेत्र की उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि की है । इसी तरह, *देवी (2015)* ने अपने अध्ययन में भारत में कृषि ऋण के महत्व पर प्रकाश डाला और पाया कि संस्थागत ऋण ने भारतीय किसानों को उत्पादन में वृद्धि और जोखिम प्रबंधन में सहायता की है। **बाबा, वानी, जरगर, और भट (2015)** ने जम्मू और कश्मीर में कृषि पर संस्थागत ऋण के प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि ऋण की उपलब्धता ने किसानों को नवीनतम तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करने में मदद की, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। कार्तिका (2012) ने केरल में कृषि उत्पादन पर संस्थागत ऋण के प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि संस्थागत ऋण ने किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों को उन्नत करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की । वेदमूर्ति, (2015) आय और जनसंख्या में वृद्धि के कारण दूध की मांग में वृद्धि हुई है, फिर भी डेयरी क्षेत्र में विकास की मौजूदा गति प्रत्याशित जरूरतों को पूरा करने में कम रही। इस वृद्धि को उच्च पथ पर ले जाने के लिए, एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता सामने आई: पशु उत्पादकता में वृद्धि। पहचानी गई रणनीतियों में, पर्याप्त संस्थागत ऋण सहायता महत्वपूर्ण थी, जो किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए सशक्त बनाती थी। कर्नाटक के शिमोगा मिल्क जोन में किए गए एक अध्ययन में डेयरी ऋण वितरण, वसूली प्रदर्शन और उपयोग की जांच की गई। चिंताजनक बात यह है कि डेयरी क्षेत्र को आवंटित ऋण अपने महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान से काफी पीछे रह गया, निर्धारित संवितरण लक्ष्यों को प्राप्त करने में 50% की कमी आई। अन्य क्षेत्रों की तुलना में पुनर्प्राप्ति दरें उल्लेखनीय रूप से कम थीं, ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनुत्पादक उद्देश्यों की ओर चला गया। इसने एक रणनीतिक नीति ढांचे की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया, जो डेयरी क्षेत्र को उच्च ऋण आवंटन का निर्देश देता है, जबकि इसके उपयोग की सख्ती से निगरानी करता है, जिससे बेहतर वसूली सुनिश्चित होती है और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है। *नायर, केएन, और सिंह,* जी. (2016) पेपर का उद्देश्य कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन और इसके सतत विकास के बीच अंतर्संबंध का पता लगाना है। परीक्षा के दौरान, कृषि में संस्थानों, प्रौद्योगिकी और संगठनात्मक परिवर्तनों के बीच बातचीत पर



प्रकाश डालने का इरादा था। संरचनात्मक परिवर्तनों की जांच (1) भिम जोत के आकार वितरण में परिवर्तन और (2) पश्धन, कृषि मशीनरी, उपकरण और सिंचाई जैसी अन्य उत्पादक संपत्तियों में संशोधन के माध्यम से की गई। इसके अतिरिक्त, संरचनात्मक परिवर्तन के प्रभाव (1) कृषि के भीतर लाभप्रदता में गिरावट और आजीविका के लिए इसके निहितार्थ, जिसमें कृषि से गैर-कृषि क्षेत्रों में श्रम का प्रवास शामिल है, (2) कृषि के भीतर अत्यधिक पूंजीकरण की घटना, और (3))) बढ़ी हुई ऊर्जा खपत और सतत विकास के लिए इसके प्रतिकृल प्रभावों की जांच की जानी थी। *मंडल. (2019)* के अध्ययन से पता चलता है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद गरीब किरायेदारों के प्रति शोषणकारी प्रकृति के कारण कृषि भूमि पट्टे को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन इसके परिणामस्वरूप, बडी संख्या में भूमिहीन परिवार अनौपचारिक भूमि पट्टे पर निर्भर हो गए। अध्ययन में पाया गया कि उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक भूमि पट्टे प्रणाली व्यापक रूप से प्रचलित है। व्यावसायिक कृषि क्षेत्रों में भूमि आमतौर पर छोटे भूमि मालिकों से समृद्ध किरायेदारों द्वारा निश्चित-मृल्य किराये के समझौते के तहत पट्टे पर ली जाती है। दूसरी ओर, जीविका के लिए कृषि क्षेत्रों में भूमि उच्च जाति के समृद्ध भूमि मालिकों से साझेदारी व्यवस्था के तहत पट्टे पर ली जाती है। यह भी पाया गया कि पट्टे के समझौते के संबंध में कोई औपचारिक दस्तावेज़ीकरण नहीं होने के कारण, किरायेदार सरकार द्वारा किसानों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों का लाभ नहीं उठा सके। कुमार, एस. (2020) ने उत्तर प्रदेश में कृषि अवसंरचना और जलवायु परिवर्तन का फसल विविधीकरण पर प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि फसल पैटर्न में खाद्यान्नों से उच्च मूल्य फसलों की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। लेकिन यह बदलाव सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं था। कृषि अवसंरचना सूचकांक (AII) और फसल विविधीकरण सूचकांक (SID) ने यह दर्शाया कि बेहतर कृषि अवसंरचना और समुचित जलवाय कारकों ने फसल विविधीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रैंडम इफेक्ट मॉडल ने पृष्टि की कि AII, उर्वरक, वर्षा परिवर्तनशीलता, न्यूनतम तापमान और साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में फसल विविधीकरण के प्रमुख निर्धारक रहे हैं। कुमारी, आर. (2018) के अध्ययन में पाया गया कि कृषि क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से निम्न-आय वाले देशों में। उन्होंने पाया कि उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था अभी भी अनाजों द्वारा प्रभुत्वशाली है। हालांकि, बेहतर वर्षा, सिंचाई सुविधाएं, व्यापार की अनुकुल शर्तें, सडक विकास और उर्वरक उपयोग ने राज्य में कृषि विकास को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। *बाजपेई, एन., और वोलावका,* एन. (2005) ने उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और समस्याओं की पहचान की और उच्च स्तर की कृषि वृद्धि प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक निवेश और राज्य सरकार के ध्यान की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें सिंचाई पर अधिक ध्यान, कृषि अनसंधान और विकास में व्यय, फसलों का विविधीकरण, और कृषि आधारित उद्योगों का प्रमोशन शामिल है।

उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में व्यावसायिक फसलों के विकास में संस्थागत ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका है। अध्ययन दर्शाता है कि संस्थागत ऋण से कृषि उत्पादकता में वृद्धि, आधुनिक तकनीकों का उपयोग और किसानों की आय में सुधार होता है, जिससे क्षेत्रीय कृषि विकास को बढ़ावा मिलता है।



संरचनात्मक समीकरण प्रतिरूप और उसके प्रभाव का अनुमान

हमने इस मॉडल से पाया कि "बस्ती जनपद में व्यावसायिक फसल विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करने की अनुसंधान पद्धित में कारक विश्लेषण के लिए एएमओएस का उपयोग एक मजबूत दृष्टिकोण प्रदान करता है जिससे इस घटना को प्रभावित करने वाले अंतर्निहित कारकों को समझा जा सकता है। अनुसंधान पद्धित में एएमओएस का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसका अनुसरण किया जा रहा है।

डेटा तैयार करना: विभिन्न कारकों जैसे सरकारी नीतियों, वित्तीय समावेशन पहल, तकनीकी प्रगति, बाजार लिंकेज, जोखिम प्रबंधन रणनीतियों, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक फसल विकास में ऋण की भूमिका से संबंधित डेटा एकत्र किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया कि विश्लेषण के लिए डेटा ठीक से स्वरूपित और व्यवस्थित है।

मॉडल विशिष्टता: एएमओएस में एक संरचनात्मक समीकरण मॉडल (एसईएम) विकसित किया गया जो विभिन्न कारकों के बीच परिकल्पित संबंधों और व्यावसायिक फसल विकास में ऋण की भूमिका पर उनके प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। अव्यक्त चर (कारक) और उनके संबंधित संकेतक (सर्वेक्षण प्रश्न या चर) निर्दिष्ट किए गए है।

मापन मॉडल मूल्यांकन: एएमओएस का उपयोग करके मापन मॉडल की विश्वसनीयता और वैधता का आकलन किया गया। यह जांचने के लिए पृष्टिकारक कारक विश्लेषण (सीएफए) का संचालन किया गया कि देखे गए चर (संकेतक) उन अव्यक्त संरचनाओं (कारकों) को कितनी अच्छी तरह प्रतिबिंबित करते है जिन्हें वे मापने का इरादा रखते है। माप की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए कारक लोडिंग, समग्र विश्वसनीयता और निकाले गए औसत विचरण (एवीई) का मूल्यांकन किया गया है।

वांछनीय मूल्य मूल्यांकन: एएमओएस में उपलब्ध विभिन्न फिट सूचकांकों का उपयोग करके एसईएम के समग्र फिट का मूल्यांकन किया गया, जैसे कि ची-स्क्वायर, तुलनात्मक फिट इंडेक्स (सीएफआई), टकर-लुईस इंडेक्स (टीएलआई), अनुमान की मूल माध्य वर्ग त्रुटि (आरएमएसईए), और मानकीकृत मूल माध्य वर्ग अवशिष्ट (एसआरएमआर)। यह मूल्यांकन किया गया कि मॉडल डेटा को अच्छी तरह से फिट करता था और स्वीकार्य फिट के लिए स्थापित मानदंडों को पूरा करता है।

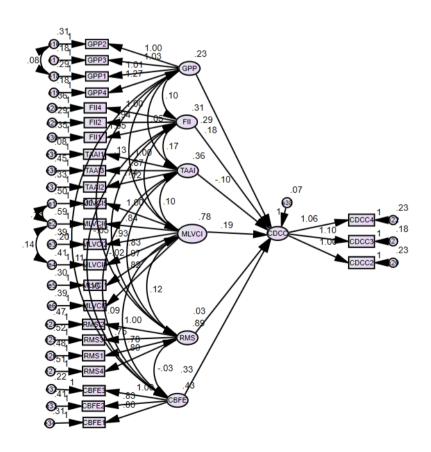
संरचनात्मक मॉडल अनुमान: अव्यक्त चर (कारकों) और व्यावसायिक फसल विकास में ऋण की भूमिका के बीच संबंधों की जांच करने के लिए संरचनात्मक मॉडल का अनुमान लगाया गया। इन रिश्तों की ताकत और दिशा को समझने के लिए पथ गुणांक का विश्लेषण किया गया। अनुमानित पथों के सांख्यिकीय महत्व और व्यावहारिक महत्व दोनों पर विचार किया गया है।



हमने पाया कि मॉडल संशोधन के लिए संशोधन सूचकांकों और सैद्धांतिक विचारों के आधार पर आवश्यकतानुसार मॉडल को पुनरावृत्तीय रूप से परिष्कृत किया गया है। पथों को जोड़कर या हटाकर, सहसंबद्ध त्रुटियों की अनुमित देकर, या वांछनीय मूल्य और व्याख्यात्मकता में सुधार के लिए अतिरिक्त चर शामिल करके मॉडल को समायोजित किया गया है।

मॉडल की व्याख्या और रिपोर्टिंग के तहत, माप मॉडल मूल्यांकन, संरचनात्मक मॉडल अनुमान और मध्यस्थता विश्लेषण सिहत एसईएम विश्लेषण से निष्कर्षों की व्याख्या की गई है। व्यावसायिक फसल विकास में कारकों और ऋण की भूमिका के बीच संबंधों की व्यापक व्याख्या प्रदान की गई थी। शोध रिपोर्ट या पांडुलिपि में परिणामों को स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से रिपोर्ट किया गया है।

अनुसंधान पद्धित में, एएमओएस को कारक विश्लेषण के लिए नियोजित करके, शोधकर्ताओं ने बस्ती जनपद में व्यावसायिक फसल विकास में ऋण की भूमिका को प्रभावित करने वाले कारकों की जिटल परस्पर क्रिया में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त की है, जो अंततः क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित नीति निर्धारण और कृषि विकास प्रयासों में योगदान करता है।





प्रतिगमन भारः (समूह संख्या 1 - डिफ़ॉल्ट मॉडल)

		अनुमान लगाना	मानक त्रुटि (एस.ई.)	महत्वपूर्ण अनुपात (सी.आर.)	संभाव्यता मान
सीडीसीसी <	जीपीपी	.292	.086	3.374	*
सीडीसीसी <	एफआईआई	.184	.060	3.085	.002
सीडीसीसी <	टीएएआई	095	.049	-1.931	.053
सीडीसीसी <	एमएलवीसीआई	.191	.030	6.427	*
सीडीसीसी <	आरएमएस	.025	.024	1.034	.301
सीडीसीसी <	सीबीएफई	.330	<u>.064</u>	5.137	*

प्रतिगमन भारों की व्याख्या

- 1. सीडीसीसी <--- जीपीपी (0.292, S.E. = 0.086, C.R. = 3.374, P < 0.05):
 - √ जीपीपी (सरकारी नीतियां और कार्यक्रम) का सीडीसीसी (व्यावसायिक फसल विकास) पर सकारात्मक प्रभाव है।
 - ✓ प्रभाव का मान 0.292 है, जो दर्शाता है कि जीपीपी में वृद्धि से व्यावसायिक फसल विकास में भी वृद्धि होती है।
 - √ यह प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है (P < 0.05), इसलिए यह प्रभाव वास्तविक और महत्वपूर्ण है।
- 2. सीडीसीसी <--- एफआईआई (0.184, S.E. = 0.060, C.R. = 3.085, P < 0.05):
 - एफ आई आई (वित्तीय समावेशन पहल) का सीडीसीसी पर सकारात्मक प्रभाव है।
- प्रभाव का मान 0.184 है, जो दर्शाता है कि एफआईआई में वृद्धि से व्यावसायिक फसल विकास में भी वृद्धि होती है।
 - यह प्रभाव भी सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है (P < 0.05), इसलिए यह प्रभाव वास्तविक और महत्वपूर्ण है।
- 3. सीडीसीसी <--- टीएएआई (-0.095, S.E. = 0.049, C.R. = -1.931, P = 0.053):
 - 🗸 टीएएआई (तकनीकी प्रगति और अवसंरचना) का सीडीसीसी पर नकारात्मक प्रभाव है।
 - ✓ प्रभाव का मान -0.095 है, जो दर्शाता है कि टीएएआई में वृद्धि से व्यावसायिक फसल विकास में कमी हो सकती है।
 - ✓ यह प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्व के किनारे पर है (P = 0.053), जो इसे कम महत्वपूर्ण बनाता है।
- 4. सीडीसीसी <--- एमएलवीसीआई (0.191, S.E. = 0.030, C.R. = 6.427, P < 0.05):
 - 🗸 एमएलवीसीआई (मार्केट लिंकेज और मूल्य श्रृंखला सुधार) का सीडीसीसी पर सकारात्मक प्रभाव है।
 - ✓ प्रभाव का मान 0.191 है, जो दर्शाता है कि एमएलवीसीआई में वृद्धि से व्यावसायिक फसल विकास में भी वृद्धि होती है।



- ✓ यह प्रभाव सांख्यिकीय रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है (P < 0.05), इसलिए यह प्रभाव वास्तविक और महत्वपूर्ण है।
- 5. सीडीसीसी <--- आरएमएस (0.025, S.E. = 0.024, C.R. = 1.034, P = 0.301):
 - ✓ आरएमएस (जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ) का सीडीसीसी पर प्रभाव बहुत कम है।
 - ✓ प्रभाव का मान 0.025 है, जो दर्शाता है कि आरएमएस का व्यावसायिक फसल विकास पर बहुत कम प्रभाव है।
 - ✓ यह प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है (P = 0.301), इसलिए इसे महत्वहीन माना जा सकता है।
- 6. सीडीसीसी <--- सीबीएफई (0.330, S.E. = 0.064, C.R. = 5.137, P < 0.05):
 - ✓ सीबीएफई (क्षमता निर्माण और वित्तीय शिक्षा) का सीडीसीसी पर सकारात्मक प्रभाव है।
 - ✓ प्रभाव का मान 0.330 है, जो दर्शाता है कि सीबीएफई में वृद्धि से व्यावसायिक फसल विकास में भी वृद्धि होती है।
 - ✓ यह प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है (P < 0.05), इसलिए यह प्रभाव वास्तविक और महत्वपूर्ण है।

विभिन्न कारकों में से, सरकारी नीतियां, वित्तीय समावेशन पहल, मार्केट लिंकेज और मूल्य श्रृंखला सुधार, और क्षमता निर्माण और वित्तीय शिक्षा का व्यावसायिक फसल विकास पर महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रभाव है। तकनीकी प्रगति और अवसंरचना का प्रभाव सीमांत नकारात्मक है, जबिक जोखिम प्रबंधन रणनीतियों का प्रभाव महत्वहीन है। यह अध्ययन बस्ती जनपद में व्यावसायिक फसलों के विकास के लिए इन कारकों की भूमिका को रेखांकित करता है।

अनुमान

प्रतिगमन विश्लेषण विभिन्न कारकों (सरकारी नीतियां और कार्यक्रम - जीपीपी, वित्तीय समावेशन पहल - एफआईआई, तकनीकी प्रगति और कृषि नवाचार - टीएएआई, बाजार लिंकेज और मूल्य श्रृंखला एकीकरण - एमएलवीसीआई, जोखिम प्रबंधन रणनीतियां - आरएमएस, और) के बीच संबंधों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। क्षमता निर्माण और किसान शिक्षा - सीबीएफई) और बस्ती जनपद में व्यावसायिक फसलों (सीडीसीसी) के विकास में संस्थागत ऋण की भूमिका। सकारात्मक जुड़ाव के साथ शुरुआत करते हुए, विश्लेषण से पता चलता है कि सरकारी नीतियां और कार्यक्रम (जीपीपी), वित्तीय समावेशन पहल (एफआईआई), बाजार लिंकेज और मूल्य श्रृंखला एकीकरण (एमएलवीसीआई), और क्षमता निर्माण और किसान शिक्षा (सीबीएफई) संस्थागत भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। व्यावसायिक फसलों के विकास को बढ़ावा देने में श्रेय। जीपीपी, जो सरकार की कृषि नीतियों और कार्यक्रमों को शामिल करती है, सीडीसीसी के साथ पर्याप्त सकारात्मक संबंध प्रदर्शित करती है। इससे पता चलता है कि सरकार द्वारा कार्यान्वित सहायक नीतियां और कार्यक्रम बस्ती जनपद में किसानों की वित्तीय जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करते हैं. जिससे व्यावसायिक



फसल की खेती के लिए संस्थागत ऋण तक उनकी पहुंच बढ़ जाती है। इसी तरह, एफआईआई, जो किसानों के लिए वित्तीय पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई पहल है, सीडीसीसी पर एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करती है, जो किसानों को व्यावसायिक फसल उत्पादन के लिए ऋण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों और वैकल्पिक वित्तीय तंत्र के महत्व को रेखांकित करती है। एमएलवीसीआई, बाजार संबंधों और मूल्य श्रृंखला एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सीडीसीसी के एक और महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता के रूप में उभरता है, जो सुझाव देता है कि बाजार के बुनियादी ढांचे में निवेश और बेहतर बाजार पहुंच किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर कीमतें प्राप्त करने में सक्षम बनाकर व्यावसायिक फसलों के विकास में योगदान करती है। इसके अतिरिक्त, सीबीएफई, जिसमें क्षमता-निर्माण पहल और किसान शिक्षा कार्यक्रम शामिल हैं, का सीडीसीसी के साथ एक महत्वपूर्ण सकारात्मक जुड़ाव पाया गया है, जो संस्थागत ऋण का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ किसानों को सशक्त बनाने में विस्तार सेवाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

इसके विपरीत, विश्लेषण उन कारकों की भी पहचान करता है जो सीडीसीसी के साथ अपने संबंधों में या तो सीमांत महत्व या गैर-महत्व प्रदर्शित करते हैं। टीएएआई, तकनीकी प्रगति और कृषि नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सीडीसीसी के साथ एक मामूली महत्वपूर्ण नकारात्मक जुड़ाव दर्शाता है। हालांकि यह उल्टा लग सकता है, लेकिन यह सुझाव देता है कि यद्यपि तकनीकी प्रगति कृषि उत्पादकता और दक्षता के लिए आवश्यक है, बस्ती जनपद में व्यावसायिक फसल विकास में संस्थागत ऋण की भूमिका पर उनका सीधा प्रभाव सीमित हो सकता है या संभावित रूप से अन्य कारकों द्वारा ऑफसेट किया जा सकता है। इसके अलावा, आरएमएस, जो जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को शामिल करता है, का सीडीसीसी के साथ एक गैर-महत्वपूर्ण संबंध पाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यावसायिक फसल की खेती से जुड़े वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन पहल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ऐसे उद्देश्यों के लिए संस्थागत ऋण तक किसानों की पहुंच पर उनका प्रभाव बस्ती जनपद के संदर्भ में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है।

इसलिए, प्रतिगमन विश्लेषण बस्ती जनपद में व्यावसायिक फसलों के विकास में संस्थागत ऋण की भूमिका को आकार देने वाली बहुमुखी गतिशीलता में सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह संस्थागत ऋण तक किसानों की पहुंच बढ़ाने और उन्हें व्यावसायिक फसल की खेती के लिए इसकी क्षमता का दोहन करने के लिए सशक्त बनाने में सहायक सरकारी नीतियों, वित्तीय समावेशन पहल, बाजार संपर्क और क्षमता निर्माण प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है। हालाँकि, यह तकनीकी अपनाने और जोखिम प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए आगे के शोध और लिक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है, जिससे क्षेत्र में सतत कृषि विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में व्यवसायिक फसलों के विकास में संस्थागत ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका विश्लेषण के अनुसार स्पष्ट हो रही है। एएमओएस और इसके प्रभाव का अनुमान, जिसमें सरकारी नीतियां, वित्तीय समावेशन पहल, तकनीकी प्रगति, और बाजार लिंकेज शामिल हैं, दिखाता है कि ऋण का उपयोग कैसे व्यवसायिक फसलों के विकास को बढ़ावा देता है। यह अनुसंधान पद्धित द्वारा आवश्यक चर संबंधों का निर्धारण करती है और उत्तर प्रदेश के कृषि संवर्धन में ऋण की प्रासंगिकता को समझने में मदद करती है।



निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक फसलों के विकास में संस्थागत ऋण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन बस्ती जनपद के विशेष संदर्भ में इस भूमिका का विश्लेषण करेगा और किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं, चुनौतियों और संस्थागत ऋण के प्रभाव पर विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। अंततः, इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष न केवल नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी होंगे, बल्कि क्षेत्रीय कृषि विकास के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। संस्थागत ऋण की प्रभावशीलता को समझना और इसे बेहतर बनाने के उपाय ढूंढना, व्यावसायिक फसल उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय में सुधार के लिए आवश्यक है। इस प्रकार, इस अध्ययन के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में व्यावसायिक फसल विकास में संस्थागत ऋण की भूमिका को समझने और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक नीतिगत सुझाव प्रदान करने का प्रयास करेंगे।

संदर्भ

- 1. सियाल, एम. एच., अवान, एम. एस., & वकास, एम. (2011). कृषि उत्पादन पर संस्थागत ऋण की भूमिका: पाकिस्तान का एक समय श्रृंखला विश्लेषण।
- 2. फरीदी, एम. जेड., चौधरी, एम. ओ., & ताहिर, एन. (2015). संस्थागत ऋण और कृषि उत्पादकता: पाकिस्तान से साक्ष्य। *पाकिस्तान जर्नल ऑफ लाइफ एंड सोशल साइंसेज*, 13(3), 183-188।
- 3. अहंगर, जी. बी., गनी, ए. एच., & पैडर, एम. जे. (2013). भारत में कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण पर एक अध्ययन। वर्तमान शोध और अकादिमक समीक्षा के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 1(4), 72-80।
- 4. कुमार, ए., सिंह, के. एम., & सिन्हा, एस. (2010). भारत में कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण: स्थिति, प्रदर्शन और निर्धारक। कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान समीक्षा, 23(2), 253-264.
- 5. खालिद बशीर, एम., & महमूद, वाई. (2010). संस्थागत ऋण और चावल उत्पादकता: जिला लाहौर, पाकिस्तान का एक केस अध्ययन। *चीन कृषि आर्थिक समीक्षा*, 2(4), 412-419।
- 6. हुसैन, ए., अली, एम., बिलाल, एम., & नवाज़, आई. (2015). पाकिस्तान में कृषि उत्पादन पर संस्थागत ऋण का प्रभाव: एक समय श्रृंखला विश्लेषण। *वर्ल्ड एप्लाइड साइंसेज जर्नल*, 33(7), 1118-1124।
- 7. खान, ए., आज़म, एम. एफ., & क़मर, डब्ल्यू. (2015). संस्थागत ऋण और कृषि उत्पादन: पाकिस्तान से अनुभवजन्य साक्ष्य। *जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट*, 6(7), 116।
- 8. अयाज़, एस., & हुसैन, ज़ेड. (2011). कृषि क्षेत्र की उत्पादन क्षमता पर संस्थागत ऋण का प्रभाव: जिला फैसलाबाद का एक केस अध्ययन। *पाकिस्तान आर्थिक और सामाजिक समीक्षा*, 149-162।
- 9. देवी, एस. (2015). भारत में कृषि ऋण. इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड लॉ, 2(7), 1-91
- 10. बाबा, एस. एच., वानी, एम. एच., जरगर, बी. ए., & भट, ए. (2015). डीएस अंतराल, उपयोग पैटर्न और जम्मू और कश्मीर में कृषि पर संस्थागत ऋण का प्रभाव। इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, 3(9), 1-9।
- 11. कार्तिका, वी. (2012). केरल में कृषि उत्पादन पर संस्थागत ऋण का प्रभाव (डॉक्टरेट शोध प्रबंध, ग्रामीण बैंकिंग और वित्त प्रबंधन विभाग, सीसीपीएम, वेल्लानिक्कारा)।
- 12. अहमद, एन. (2011). कृषि उत्पादन पर संस्थागत ऋण का प्रभाव। *सैद्धांतिक और व्यावहारिक अर्थशास्त्र*, 42, 469-485।
- 13. वेदमूर्ति, केबी, ढाका, जेपी, और सिरोही, एस. (2015) । कर्नाटक में डेयरी फार्मिंग के लिए संस्थागत ऋण का विश्लेषण: शिमोगा मिल्क जोन का एक अध्ययन। *इंडियन जर्नल ऑफ. डेयरी विज्ञान , 68* (3), 282-286.
- 14. नायर, केएन, और सिंह, जी. (2016)। पंजाब में कृषि के विकास और परिवर्तन में तकनीकी और संस्थागत परिवर्तनों की भूमिका। विकासशील अर्थव्यवस्था का आर्थिक परिवर्तन: पंजाब, भारत का अनुभव, 29-52।

Vol 7, Issue 5, 2024 Impact Factor: 5.099 DOI: https://doi.org/10.31426/ijamsr.2024.7.5.7313



International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

- 15. मंडल, एस., मिश्रा, जी. वी., नकवी, एस. एम. ए., और कुमार, एन. (2019). उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि पट्टे की स्थितिजन्य विश्लेषण। *भूमि उपयोग नीति*, 88, 104106.
- 16. कुमारी, आर. (2018). तेजी से प्रगति कर रहा है: उत्तर प्रदेश, भारत में कृषि विकास के स्रोत और प्रेरक। अंतर्राष्ट्रीय कृषि संसाधन, शासन और पारिस्थितिकी पत्रिका, 14(1), 20-44।
- 17. बाजपेई, एन., और वोलावका, एन. (2005). उत्तर प्रदेश में कृषि प्रदर्शन: एक ऐतिहासिक खाता।